दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

जनवरी (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **5**

- छात्र आदित्य चौरसिया की अक्षय ऊर्जा पर बनाई पेंटिंग राष्ट्रीय स्तर पर हुई चयनित एवं पुरस्कृत 5
- आरडीए की कॉलोनी में आवास खरीदी पर पत्रकारों को मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट 5
- राज्यपाल ने राजभवन छत्तीसगढ़ की नवीन वेबसाइट का किया लोकार्पण 5
- छत्तीसगढ़ में दो नये अभियान की शुरुआत 6
- मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली का किया शुभारंभ 7
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ हरित परिषद की प्रथम बैठक 7
- राज्य के 2201 गौठान हुए स्वावलंबी 8
- देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में प्रदेश चौथे क्रम पर 8
- छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-श्रमिक सेवा के लिये मिला गोल्डन अवार्ड 9
- छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के संशोधन विधेयक-2021 10

नोट :

- छत्तीसगढ़ में रैली कोसा के समर्थन मूल्य पर क्रय का निर्णय 10
- राज्य वीरता पुरस्कार के लिये अमन व शौर्य का चयन 11
- राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर हस्ताक्षर किया 11
- सुकमा ज़िले में 'रोको अउ टोको अभियान'का शुभारंभ 11
- छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन 12
- ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ 12
- जांजगीर-चांपा ज़िला सीएमआर में चावल जमा कराने में प्रदेश में अव्वल 13
- आईआईआईटी-नया रायपुर के निदेशक को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 13
- राज्यपाल ने राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का किया विमोचन 14
- छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति गठित 14
- एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ रायपुर पुलिस का सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान 15
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता अमिता ने की बर्फीली यूटी कांगरी चोटी पर चढ़ाई 15
- राज्यपाल ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक पर किये हस्ताक्षर 16
- मुख्यमंत्री ने जशपुर के पर्यटन और जैव-विविधता पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया 16

नोट :

- मुख्यमंत्री ने राजधानी में किया छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन के कार्यालय का शुभारंभ 17
- मुख्यमंत्री ने किया कहानी संग्रह 'विशिष्ट पराग' का विमोचन 17
- पीएमजीएसवाइ में सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर 18
- गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी कई नई सौगातें 18
- श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर में उपलब्ध दवाओं की मूल्य सूची पुस्तिका का विमोचन 19
- राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और बहादुर बच्चों को किया सम्मानित 20
- प्रदेश में सबसे अधिक रायगढ़ जिले के 279 गोठान हुए स्वावलंबी 21
- रायपुर जिले में कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू 21
- शहीदों के सम्मान में रायपुर में प्रज्वलित होगी 'छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति' 22

The Vision

नोट :

छत्तीसगढ़

छात्र आदित्य चौरसिया की अक्षय ऊर्जा पर बनाई पेंटिंग राष्ट्रीय स्तर पर हुई चयनित एवं पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

- 1 जनवरी, 2022 को रायपुर के आरडी तिवारी आत्मानंद विद्यालय के कक्षा दसवीं के छात्र आदित्य चौरसिया द्वारा ऊर्जा पर बनाई गई पेंटिंग छत्तीसगढ़ राज्य से नेशनल स्तर पर चयनित एवं पुरस्कृत हुई है।

प्रमुख बिंदु

- इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिये राष्ट्रपति द्वारा आदित्य चौरसिया को जनवरी माह में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में अपने माता-पिता के साथ छात्र आदित्य चौरसिया ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल पर बनाई गई पेंटिंग भी भेंट की।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदित्य को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ ही 50 हजार रुपए का पुरस्कार जीतने पर बधाई और शुभकामनाएँ दी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आदित्य चौरसिया की पेंटिंग का राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होना, राज्य के लिये गौरव की बात है। आदित्य की इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है।

आरडीए की कॉलोनी में आवास खरीदी पर पत्रकारों को मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट

चर्चा में क्यों ?

- 1 जनवरी, 2022 को छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में रायपुर विकास प्राधिकरण की कॉलोनी में आवास खरीदी पर पत्रकारों को 15 प्रतिशत की छूट की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब में स्थापित जिम का भी लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने सांध्य दैनिक 'अग्रदूत'में प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले छत्तीसगढ़ी व्यंग्य स्तंभ 'झंगलू-मंगलू के गोठ'के किताब के रूप में संकलन और प्रकाशन के लिये दो लाख रुपए देने की भी घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कोरोना काल में मरीजों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले एम्स रायपुर के निदेशक डॉ. नितिन एम. नागरकर को सम्मानित किया।
- छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सचिव गुरुचरण सिंह होरा को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।

राज्यपाल ने राजभवन छत्तीसगढ़ की नवीन वेबसाइट का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 1 जनवरी, 2022 को छतीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन छत्तीसगढ़ की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन छत्तीसगढ़ के वार्षिक कैलेंडर 2022 का विमोचन भी किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राजभवन छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में राज्यपाल सुश्री उइके का जीवन परिचय, उनकी गतिविधियों, कार्यक्रमों, संवैधानिक दायित्व, कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल के दायित्व, राजभवन सचिवालय की संपूर्ण जानकारी एवं विश्वविद्यालयों से संबंधित जानकारी, राज्यपाल से भेंट-मुलाकात के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रक्रिया का विवरण भी दिया गया है।
- वेबसाइट में पूर्व राज्यपालों के जीवन परिचय, महत्त्वपूर्ण अवसरों पर राज्यपाल के भाषण फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिपिंग, सूचना के अधिकार एवं कर्मचारीयों संबंधी जानकारी आदि भी शामिल की गई है।

छत्तीसगढ़ में दो नये अभियान की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

- 1 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दो नए अभियान शुरू किये। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इन दोनों अभियानों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- ज़िला मुख्यालय अंबिकापुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम से दोनों मंत्रियों ने वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़ कर बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिये सौ दिवसीय अभियान तथा शाला त्यागी बच्चों के लिये व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम-स्किल हब एनिशिएटिव कार्यक्रम की शुरुआत की।
- स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दोनों योजनाओं के शुभारंभ की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने से बच्चों के लर्निंग लॉस को कम करने के लिये राज्य व्यापी सौ दिनों का पठन एवं गणितीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
- इस सौ दिवसीय कार्यक्रम को तीन स्तरों के लिये तैयार किया गया है। पहला स्तर आंगनबाड़ी से कक्षा दूसरी तक के बच्चे, दूसरे स्तर में कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक और तीसरे स्तर में कक्षा छठवीं से आठवीं तक के बच्चों को शामिल किया गया है।
- यह कार्यक्रम 14 सप्ताहों में विभाजित है। प्रत्येक सप्ताह के लिये भाषा और गणित में अलग-अलग थीम साझा की जाएगी। इस थीम को बहुत अच्छे से कक्षा के सभी बच्चों में पूरे सप्ताह अभ्यास करवाते हुए उन्हें अनिवार्यत: दक्ष बनाए जाने के लिये सभी आवश्यक प्रयास शिक्षकों द्वारा किये जाएंगे।
- कक्षा के भीतर और बाहर समुदाय के सहयोग से सप्ताह के लिये निर्धारित सामग्री का अभ्यास कराया जाएगा।
- मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिये स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम राज्य में पहली बार विद्यालय स्तर पर समग्र शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित कौशल केंद्र की पहल की जा रही है।
- इसके अंतर्गत राज्य में कुल 86 विद्यालयों का चयन भारत शासन द्वारा किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश के 17 ज़िलों के 18 विद्यालयों का चयन किया गया है।
- कौशल केंद्र के माध्यम से 15 से 29 आयु वर्ग के शाला छोड़ने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध व्यावसायिक कोर्स पर कौशल प्रशिक्षण प्रदाय किया जाएगा, ताकि उनकी क्षमता का विकास हो सके और वे भविष्य में इन सीखे हुए कौशल का उपयोग जीविकोपार्जन या अन्य शैक्षिणिक गतिविधियों में कर सकें। इसके साथ ही कौशल केंद्र के माध्यम से शिक्षा से बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को पुन: शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य भी हो सकेगा।
- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम 40 विद्यार्थियों का एक बैच होगा। प्रशिक्षण से सर्टिफिकेशन कार्यक्रम की कुल अवधि 6 माह होगी। प्रशिक्षण प्रत्येक दिवस विद्यालय अवधि के बाद लगभग दो घंटे और साप्ताहिक अवकाश में संचालित किया जाएगा।
- स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिये रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिये संचालित किया जा रहा है। इसमें आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को भी जोड़ा गया है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 3 जनवरी, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कर्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर (5382 वर्ग फीट) तक के आवासीय प्लाट्स पर भवन निर्माण के लिये मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस प्रणाली के द्वारा जारी की गई प्रथम भवन अनुज्ञा रायपुर के दलदलसिवनी निवासी आवेदक श्रीमती चेतन देव साहू को प्रदान की।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रणाली से राज्य के शहरों के विकास में तेजी आएगी और नागरिकों को एक बड़ी समस्या का प्रभावी समाधान मिलेगा।
- राज्य के नागरिक जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिये भवन अनुज्ञा एक अहम प्रक्रिया है। पहले यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी नागरिकों को इस सुविधा प्राप्ति के लिए काफी परेशानी हुआ करती थी। क्योंकि ये प्रकिया पूरी होने में लंबा समय लगा करता था एवं नक्शा पास कराने के लिये यह प्रकिया कई अधिकारियों तक पहुँचा करती थी और उसके बाद नागरिक को घर बनाने के लिये भवन अनुज्ञा मिलती थी।
- अब यह प्रकिया सब मानव हस्तक्षेप रहित होगी और जल्द से जल्द पूर्ण होगी। यदि आवेदक के पास सभी सही दस्तावेज़ हैं तो अवेदक को एक रुपए का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अब उनको अपना घर बनाने के लिये कहीं भी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ हरित परिषद की प्रथम बैठक

चर्चा में क्यों ?

- 3 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में प्रदेश में रि-जेनरेटिव डेवलपमेंट को गति प्रदान करने के लिये गठित छत्तीसगढ़ हरित परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पर्यावरणीय मुद्दे को हल करने के लिये परिषद के दृष्टिकोण और मुख्य गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- रि-जेनरेटिव डेवलपमेंट (पुनरुत्पादन विकास), सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अधिक प्रगतिशील अवधारणा है, जिसमें उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग के साथ-साथ संसाधनों की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ न्यू एज ग्रीन इकॉनमी के तहत लाईवलीहुड से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि के लिये कार्य किया जाता है।
- मुख्यमंत्री ने बैठक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की हरित राज्य के रूप में ब्रांडिंग, जैविक उत्पादों के मार्केट लिंकेज, प्रशिक्षण के माध्यम से स्व-सहायता समूहों की क्षमता निर्माण, ज़िलों की विशेषता के अनुसार विकास और स्थानीय निवासियों को जोड़कर आर्थिक मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर बल दिया।
- उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ संभवत: देश का पहला राज्य है, जहाँ हरित परिषद का गठन किया गया है। हरित परिषद के माध्यम से राज्य में हरित एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था को और अधिक मज़बूत करने के प्रयास किये जाएंगे।
- सरकार की पहल में स्थायी वन, औषधीय, हर्बल और अन्य उत्पादों को बाज़ार से जोड़ने के लिये महिला स्व-सहायता समूहों की क्षमता का निर्माण, छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ कंपनियों को आमंत्रित करना और राज्य के भीतर कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू करना शामिल होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिये पर्यावरण हितैषी अनेक योजनाएँ, जैसे 'सुराजी गाँव योजना'के अंतर्गत 'नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना', 'गोधन न्याय योजना', गोठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का कार्य, 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना'के अंतर्गत वन क्षेत्रों में विस्तार के साथ-साथ स्थानीय वनवासियों की आय में वृद्धि, लघु वनोपजों में वेल्यू एडिशन प्रारंभ की गई हैं, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तीकरण को गति दे रही हैं।

नोट :

- कार्बन उत्सर्जन के संबंध में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। पराली न जलाकर उसका उपयोग चारे के रूप में करने से कार्बन उत्सर्जन (प्रदूषण) में कमी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है।
- मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर ज़िले में रि-जेनरेटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिये एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाए, ज़िलों की विशेषता का चिह्नांकन कर विशेषज्ञों की सहायता से वहाँ विकास के कार्य किये जाएँ।
- उन्होंने छत्तीसगढ़ की ब्रांडिंग की दिशा में भी प्रयास करने के निर्देश दिये। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में इस तरह का प्रगतिशील कदम उठाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा।

राज्य के 2201 गौठान हुए स्वावलंबी

चर्चा में क्यों ?

- 6 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से महत्त्वपूर्ण 'सुराजी गाँव योजना' के 'गरूवा' घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 7889 गौठानों में से 2201 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- स्वावलंबी गौठान गोबर खरीदी से लेकर वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण के लिये स्वयं के पास उपलब्ध राशि का उपयोग करने लगे हैं।
- रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 249 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। दूसरे नंबर पर महासमुंद एवं कोरबा जिले हैं जिनके 170-170 गौठान तथा तीसरे क्रम पर कबीरधाम जिले में 141 गौठान स्वावलंबी हुए हैं।
- जांजगीर-चांपा में 105, कांकेर में 104, राजनांदगाँव जिले में 101, दुर्ग में 86, बलौबाजार में 84, धमतरी में 80, बिलासपुर में 76, रायपुर में 75, कोरिया में 73, जशपुर में 70, बालोद में 67, बेमेतरा में 66, सरगुजा में 65, मुंगेली में 62, सूरजपुर में 56, बलरामपुर में 55, सुकमा जिले में 52, कोंडागाँव में 46, दंतेवाड़ा व बस्तर में 35-35, गरियाबंद व गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 25-25, बीजापुर में 22 तथा नारायणपुर में 6 गौठान स्वावलंबी बन चुके हैं।
- गौरतलब है कि राज्य में पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक 10591 गाँवों में गौठान के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें से 7889 गौठानों का निर्माण पूरा हो चुका है और वहाँ पर गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण सहित अन्य आयमूलक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं।
- गौठानों में पशुधन के देखरेख, चारे-पानी एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर पशुधन के चारे के लिए किसानों द्वारा पैरा दान किया जा रहा है।
- अब तक 7 लाख 32 हजार 886 क्विंटल से अधिक पैरा गौठानों में दान के माध्यम से संग्रहीत किया गया है। इसके अलावा गौठानों में पशुओं के लिये हरे चारे के इंतजाम के लिये हाईब्रिड नेपियर ग्रास का रोपण एवं अन्य चारे की बुआई भी की गई है।

देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में प्रदेश चौथे क्रम पर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) संगठन द्वारा जारी किये गए बेरोजगारी के आँकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.1 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है।

प्रमुख बिंदु

- दिसंबर 2021 की स्थिति के अध्ययन के बाद सीएमआईई द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर कर्नाटक में 1.4 प्रतिशत और सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 34.1 प्रतिशत बताई गई है।

नोट :

- आँकड़ों के मुताबिक गुजरात 1.6 प्रतिशत के साथ कम बेरोजगारी वाला दूसरा राज्य है, जबकि पड़ोसी ओडिशा 1.6 प्रतिशत के साथ तीसरे क्रम पर एवं मध्य प्रदेश 3.4 प्रतिशत के साथ 07 वें क्रम पर है।
- उत्तर प्रदेश में 4.9 प्रतिशत की बेराजगारी दर है। असम 5.8 प्रतिशत के साथ 12वें क्रम पर है। राजस्थान में 27.1 प्रतिशत, झारखंड में 17.3 और बिहार में 16 प्रतिशत बेरोजगारी की दर है।
- रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जनवरी 2021 की स्थिति में देश में बेरोजगारी दर 6.52 फीसदी थी, जिसमें शहरी बेरोजगारी 8.9 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 5.81 प्रतिशत थी, वहीं दिसंबर 2021 की स्थिति में देश में बेरोजगारी की दर 7.7 प्रतिशत रही जिसमें शहरी बेरोजगारी 9.1 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1 प्रतिशत रही।
- छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गाँवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- इसी मॉडल के अंतर्गत गाँवों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये सुराजी गाँव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही।
- गौरतलब है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन 45 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में सतत् अध्ययन करके डेटाबेस का निर्माण करता आया है और इसके द्वारा जारी आँकड़ों को प्रामाणिक माना जाता है।

छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-श्रमिक सेवा के लिये मिला गोल्डन अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

- 7 जनवरी, 2022 को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिये भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को श्रमिक सेवा के लिये गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, हैदराबाद में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत) डॉ. जितेंद्र सिंह से छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के सचिव एलेक्स पॉल मेनन और श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम ने ग्रहण किया।
- छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-गवर्नेंस के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई-सर्विसेज श्रेणी में ई-श्रमिक सेवा के लिये गोल्डन अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड के साथ 2 लाख रुपए की राशि दी गई है।
- छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा ई-श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर और लक्ष्य के आधार पर तीसरे स्थान पर है।
- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।
- गौरतलब है कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा हर साल ई-गवर्नेंस में नवाचार के लिये केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा ज़िलों को पुरस्कृत किया जाता है।
- वर्ष 2020-21 के लिये एक्सिलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिवर्सलाईजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई-सर्विसेज, एक्सिलेंस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन ई-गवर्नेंस, आउटस्टेंडिंग रिसर्च ऑन सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज बाय एकेडेमिक/रिसर्च इंस्टिट्यूशन, एक्सिलेंस इन एडॉप्टिंग इमरजिंग टेक्नोलॉजी और यूज़ ऑफ आईसीटी इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है।

नोट :

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के संशोधन विधेयक-2021

चर्चा में क्यों ?

- 11 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम में संशोधन के लिये प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत अधिनियम की धारा 2, 3, 4, 6 और 16 में आंशिक संशोधन किया गया है।
- इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग में एक उपाध्यक्ष का पद निर्मित किया गया है। संशोधन के बाद धारा 3, 4, 6 और 16 में शब्द 'अध्यक्ष'के पश्चात् शब्द 'उपाध्यक्ष'अंत:स्थापित किया जाएगा।
- यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 के तहत 7 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, जिसके तहत 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। नए संशोधन में प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग में 7 सदस्य में से एक अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष का पद निर्मित करने का बिंदु शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ में रैली कोसा के समर्थन मूल्य पर क्रय का निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 12 जनवरी, 2022 को प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ संजय शुक्ला ने बताया कि बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी-वनवासी कृषकों के हित में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि शासन के इस महत्त्वपूर्ण निर्णय से अब रैली कोसा के उत्पादन सहित प्रसंस्करण का अधिक-से-अधिक लाभ स्थानीय निवासियों को मिलेगा।
- इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में रैली कोसा के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर रोज़गार बढ़ाने के लिये भी निर्देशित किया गया है।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य कोसा उत्पादन में अग्रणी है। राज्य में दो प्रकार के कोसा का उत्पादन होता है, जिसे रैली तथा डाबा कोसा कहा जाता है। वर्तमान में रेशम विभाग द्वारा डाबा कोसा क्रय किया जाता है, परंतु रैली कोसा का क्रय व्यापारियों के माध्यम से होता है।
- इसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में उत्पादित रैली कोसा को समर्थन मूल्य पर क्रय करने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को निर्देशित किया गया है। इसका राज्य के जगदलपुर (बस्तर), दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव तथा सुकमा आदि ज़िले के आदिवासी-वनवासी कृषकों सहित निवासियों को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि रैली कोसा का उत्पादन मुख्य रूप से साल वृक्ष पर प्राकृतिक रूप से होता है। डाबा कोसा का उत्पादन अर्जुन, साजा एवं लेंडिया आदि वृक्षों पर होता है। रैली कोसा परिमाण तथा गुणवत्ता में डाबा कोसा से उत्कृष्ट है। रैली कोसा 2 सीजन (भादो तथा चैती) में होता है। भादो फसल की मात्रा तथा गुणवत्ता अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में 8 से 12 करोड़ रैली कोसा-कोकून का उत्पादन होता है। इसका औसतन मूल्य 30 से 40 करोड़ रुपए होता है। साथ ही 9 से 10 करोड़ कोकून डाबा कोसा के रूप में उत्पादन होता है, जिसका मूल्य लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए होता है।
- वर्तमान में इनमें से डाबा कोसा का क्रय रेशम विभाग द्वारा किया जाता है, परंतु रैली कोसा का क्रय व्यापारियों के माध्यम से होता है।

नोट :

राज्य वीरता पुरस्कार के लिये अमन व शौर्य का चयन

चर्चा में क्यों ?

- 12 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद ने राज्य वीरता पुरस्कार की घोषणा की। इस वर्ष यह पुरस्कार धमतरी ज़िले के शौर्य प्रताप चंद्राकर व कोरबा के अमन ज्योति जाहिरे को प्रदान किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की अध्यक्षता में ज्यूरी समिति ने यह निर्णय लिया है।
- यह पुरस्कार राजधानी रायपुर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- इन बच्चों को पुरस्कार में 15-15 हज़ार रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति-पत्र और चांदी का मेडल दिया जाएगा।
- गौरतलब है कि शौर्य प्रताप चंद्राकर ने 13 जून, 2021 को खेत में काम कर रहे लोगों को बिजली के करंट से बचाया था वहीं अमन ज्योति जाहिर ने अगस्त, 2021 में पानी के तेज बहाव में कूदकर अपने दोस्त आशीष की जान बचाई थी।

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर हस्ताक्षर किया

चर्चा में क्यों ?

- 14 जनवरी, 2022 को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन हेतु प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम (संशोधन) विधेयक को 15 दिसंबर, 2021 को पारित किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात् नई कर प्रणाली में कुछ कठिनाईयाँ सामने आई हैं।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 करदाताओं के लेखा पुस्तकों की संपरीक्षा विशेष वृत्तिक (सी.ए. आदि) से कराने संबंधी उपबंध करता है, परिणामस्वरूप करदाताओं, विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों को अतिरिक्त अनुपालन भार का सामना करना पड़ता है।
- इसके अतिरिक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में कतिपय विसंगतियाँ पाई गई थीं। साथ ही आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) लिये जाने के प्रावधान को अधिक कठोर करने की आवश्यकता है, ताकि गलत आगत कर प्रत्यय की उपलब्धता रोकी जा सके।
- उपर्युक्तानुसार यथावर्णित अनुपालन भार को कम करने, अधिनियम के प्रावधानों में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने एवं आगत कर प्रत्यय से संबंधित प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिये छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में कतिपय संशोधन का निर्णय लिया गया था।
- जी.एस.टी. काउंसिल द्वारा लिये गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 28 मार्च, 2021 से केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 प्रवृत्त है। अत: छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में भी तद्नुसार संशोधन किया जाना आवश्यक था।

सुकमा ज़िले में 'रोको अउ टोको अभियान'का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 14 जनवरी, 2022 को सुकमा ज़िले में ज़िला प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ विद पीपल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में वी द पीपल के वालेंटियर को टी-शर्ट वितरण कर 'रोको अउ टोको अभियान'का शुभारंभ किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ज़िला कलेक्टर विनीत नन्दनवार के मार्गदर्शन एवं ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी देव नारायण कश्यप की अध्यक्षता तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुकमा सी. बी. प्रसाद बंसोड़ की उपस्थिति में वालेंटियर को रोको टोको का टी-शर्ट ज़िला पंचायत कार्यालय में वितरित किया गया।
- कोविड-19 के तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप एवं संक्रमण की तेज़ गति को देखते हुए वी द पीपल के वालेंटियर के सहयोग से ज़िले की भीड़-भाड़ वाली जगहों में राहगीरों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने, कोविड-19 टीकाकरण करवाने, जागरूकता लाने हेतु रोको और टोको अभियान का शुभारंभ किया गया है।
- इस कार्यक्रम के तहत वालेंटियर्स के द्वारा मेघा फोन के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने, समाजिक दूरी का पालन करने, कोविड-19 टीकाकरण करवाने के लिये प्रेरित किया जा रहा है ।

छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन

चर्चा में क्यों ?

- 15 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने राज्य में आगामी पाँच वर्षों में 12 से 15 लाख नए रोज़गार के अवसरों का सृजन करने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन के गठन का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।
- मिशन के अन्य सदस्य संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोज़गार एवं प्रशिक्षण, संचालक मत्स्य पालन, प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन होंगे।
- मिशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उक्त नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी., ट्रिपल आई.टी. आई.आई.एम., एन.आई.टी. जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोज़गार के नए अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा।
- राज्य में विगत 3 वर्षों में सभी ज़िलों में रोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक अभिनव कार्यक्रम आरंभ किये गए हैं, जिनसे बड़ी संख्या में रोज़गार के स्थाई अवसरों का सृजन हुआ है तथा लोगों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
- छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन एवं लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन तथा वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोज़गार के नए अवसरों के सृजन की असीमित संभावनाएँ हैं।

ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 15 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पंचायत विभाग द्वारा तैयार किये गए ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल प्रमुख रूप से चार मॉड्यूल पर कार्य करने के लिये बनाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने वेब पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल प्रदेश को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा। इससे प्रदेश राजनीतिक-सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही पंचायती राज के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

नोट :

- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 11 हज़ार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केन्द्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिये प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा।
- इस पोर्टल के माध्यम से ही पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डाटा पुनरीक्षण के साथ ही विभागीय आदेश, अधिसूचना व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेज़ों के संकलन और संधारण के लिये चार मॉड्यूल उपलब्ध होंगे।
- पोर्टल के माध्यम से पंचायत विभाग के एचआरएमएस (Human Resource Management System) सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदेशभर की ग्राम पंचायतों में कार्यरत् पंचायत सचिवों के वेतन का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। एलएमएस (Learning Management System) द्वारा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा जारी पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित लर्निंग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग की जाएगी।
- पंचायत संचालनालय द्वारा विभागीय आदेशों, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों से संबंधित दस्तावेज़ों के संकलन के लिये केएमएस (Knowledge Management System) तथा ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा के आयोजन के पहले 100 बिंदुओं पर आधारभूत जानकारियों के संकलन के लिये सर्वे (Survey) मॉड्यूल भी विकसित किया गया है।

जांजगीर-चांपा ज़िला सीएमआर में चावल जमा कराने में प्रदेश में अव्वल

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मार्कफेड के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सीएमआर में चावल जमा कराने के मामले में जांजगीर-चांपा ज़िला प्रदेश में अव्वल है। ज़िले में सीएमआर के अंतर्गत नान सेंट्रल-नॉन स्टेट और एफसीआई में कुल 1,01,277 मीट्रिक टन चावल जमा कराया जा चुका है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार जांजगीर-चांपा ज़िले में उपार्जन केंद्रों से 285 राइस मिलरों द्वारा धान का उठाव किया गया है। इन मिलरों को 3,96,313 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। साथ ही 1,20,163 मीट्रिक टन के लिये परिवहन आदेश जारी किये गए हैं।
- जांजगीर-चांपा ज़िले में नॉन सेंट्रल में 10515 मीट्रिक टन, नॉन स्टेट में 9375 मीट्रिक टन, एफसीआई में 80,785 मीट्रिक टन, इस प्रकार कुल 1,01,277 मीट्रिक टन चावल जमा किया गया है।
- इसी प्रकार धमतरी ज़िला सीएमआर में चावल जमा करने के मामले में दूसरे स्थान पर है। धमतरी ज़िले में नॉन सेंट्रल में 16,722 मीट्रिक टन, नॉन स्टेट में 15,868 मीट्रिक टन तथा एफसीआई में 49,414 मीट्रिक टन, इस प्रकार कुल 82 हज़ार 03 मीट्रिक टन चावल जमा किया गया है।
- रायपुर ज़िला सीएमआर में चावल जमा कराने के मामले में तीसरे स्थान पर है। रायपुर ज़िले में नॉन सेंट्रल में 2885 मीट्रिक टन, नॉन स्टेट में 2738 मीट्रिक टन एवं एफसीआई में 75373 मीट्रिक टन, इस प्रकार कुल 80,996 मीट्रिक टन चावल जमा कराया गया है।

आईआईआईटी-नया रायपुर के निदेशक को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 17 जनवरी, 2022 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) नया रायपुर के निदेशक डॉ. प्रदीप के. सिन्हा को सोसाइटी फॉर डेटा साइंस (S4DS) द्वारा डेटा साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिये लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस पुरस्कार की घोषणा वर्चुअल मोड में आयोजित 'इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड इनोवेशन 2022 (ICDMAI 2022)' के समापन सत्र के दौरान की गई।
- उल्लेखनीय है कि डॉ. प्रदीप सिन्हा पिछले 35 सालों से आईटी प्रोफेशनल के तौर पर सेवाएँ दे रहे हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वे 6 पुस्तकें लिख चुके हैं। 2015 में ट्रिपलआईटी नया रायपुर के निर्माण में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।
- इससे पहले वे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डेक) में सुपर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नेतृत्व कर चुके हैं।
- 2019 में उन्होंने ट्रिपलआईटी में डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक तथा एमटेक प्रोग्राम शुरू करने की पहल की थी।

राज्यपाल ने राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का किया विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 18 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस वृत्तचित्र का निर्माण जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया है। राज्यपाल ने वृत्तचित्र की सराहना करते हुए कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री में राजभवन के सभी हिस्सों का रोचक प्रस्तुतीकरण किया गया है। इस वृत्तचित्र के माध्यम से आमजनों को राजभवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी।
- इस डॉक्यूमेंट्री में राजभवन के निर्माण से अब तक के राजभवन की यात्रा का वर्णन किया गया है।
- इसमें सभी राज्यपाल, राजभवन के विभिन्न भागों की अधोसंरचना- राजभवन, सचिवालय, दरबार हॉल आदि की विस्तृत जानकारी दी गई है।
- इसमें राजभवन के दोनों उद्यान, उनमें लगे पेड़-पौधों की प्रजातियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। साथ ही राजभवन के दरबार हॉल की विशेषता एवं यहाँ आयोजित विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति गठित

चर्चा में क्यों ?

- 20 जनवरी, 2022 को राज्य शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति के गठन की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष होगा।

प्रमुख बिंदु

- जारी अधिसूचना के अनुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर को छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।
- इसी प्रकार मुस्लिम धर्म ज्ञान एवं मुस्लिम कानून विशेषज्ञ के रूप में रायपुर के मौलाना कारी सैयद अशफाक अहमद, मौलाना डॉ. कारी इमरान अशरफी, मौलाना असगर मेहंदी को राज्य हज समिति का सदस्य बनाया गया है।
- मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में अनुभव रखने वाले इम्तियाज अहमद (सूरजपुर), डॉ. रूबिना अल्वी (राजनांदगांव), शमीम अख्तर (रायपुर) को सदस्य नियुक्त किया गया है।
- इसके साथ ही राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य हज कमेटी कार्यपालन अधिकारी-सचिव को पदेन सदस्य मनोनीत किया गया है।

नोट :

एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ रायपुर पुलिस का सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रायपुर पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता पर चलाए गए सप्ताहव्यापी अभियान में एक ही दिन में 1,02,468 नागरिकों द्वारा सड़क सुरक्षा के लिये संकल्प लेने को एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

- रायपुर के इन नागरिकों ने रायपुर पुलिस द्वारा 'सुनो रायपुर'थीम पर 26 दिसंबर, 2021 से 1 जनवरी, 2022 तक सप्ताह भर आयोजित किये गए इस अभिनव अभियान के दौरान एक जनवरी को सड़क सुरक्षा संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नए साल में सड़क सुरक्षा का संकल्प लिया है।
- रायपुर पुलिस द्वारा सक्रिय स्वयंसेवकों की मदद से 'सुनो रायपुर'नाम से चलाए गए इस अभियान में कई बच्चे अपने बड़ों को सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश देकर रायपुर पुलिस का समर्थन करने के लिये आगे आए थे।
- 'सुनो रायपुर'का शुभारंभ एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा 26 दिसंबर को मैग्नेटो मॉल रायपुर में जागरूकता कार्यक्रम के रूप में किया गया। उन्होंने नागरिकों से अपील की थी कि वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और लापरवाही से वाहन चलाकर या बुनियादी सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें।
- उन्होंने लोगों से किसी भी तरह के बाइक स्टंट या स्पीड ड्राइविंग का प्रयास करते समय अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचने का अनुरोध किया। लोगों को ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने के लिये सुनिश्चित करने हेतु चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।
- 'सुनो रायपुर'अभियान के दौरान रायपुर पुलिस की टीमों और 300 सक्रिय स्वयंसेवकों ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, बाज़ार क्षेत्रों, मुख्य चौकों, स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों में यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया।
- इस अभियान के दौरान दिलचस्प और शैक्षिक संदेशों वाले पैम्फलेट, तख्तियाँ, हैंडआउट्स, वीडियो स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया। इस जागरूकता अभियान के दौरान लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये रायपुर पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया।
- गौरतलब है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। अकेले रायपुर ज़िले में ही हर साल करीब 450 लोगों की मौत हो जाती है।
- इन मौतों के पीछे मुख्य कारण तेज़ गति से वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना और हेलमेट न पहनना है। बुनियादी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है।
- इस अभियान को रायपुर ऑटो डीलर्स एसोसिएशन, यंग इंडियंस, सुरक्षित भव फाउंडेशन, सिख केयर इंडिया, आभा फाउंडेशन, आवाज़ फाउंडेशन, स्पर्श एक कोशिश, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, कोपल वाणी, मिशन संभव, वक्ता मंच और सौभाग्य फाउंडेशन, मारूति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल, प्रांजल सेवा समिति जैसे कई गैर-सरकारी संगठनों और संघों के स्वयंसेवकों द्वारा समर्थन और सहयोग दिया गया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता अमिता ने की बर्फीली यूटी कांगरी चोटी पर चढ़ाई

चर्चा में क्यों ?

- 19 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा ज़िले की पर्वतारोही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता अमिता श्रीवास ने प्राचीन हिमालय के लद्दाख श्रेणी की 6070 मीटर ऊँची बर्फीली यूटी कांगरी चोटी की चढ़ाई की। उन्होंने 14 जनवरी को चढ़ाई शुरू की और 19 जनवरी को यूटी कांगरी के शिखर पर पहुँचीं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अमिता की पर्वत चोटी पर यह चौथी बड़ी चढ़ाई थी। विवेकानंद माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट माउंट आबू से वर्ष 2018 में रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने 2019 में उत्तरी सिक्किम में व पश्चिमी सिक्किम के बड़े शिखरों पर विजय हासिल की थी।
- इसके बाद 8 मार्च, 2021को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तीकरण का मिशन लेकर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। तंजानिया स्थित किलिमंजारो की 5895 मीटर ऊँची चोटी पर पहुँचने के बाद उन्होंने' गढ़बो नवा छत्तीसगढ़'का भी संदेश दिया था।
- अमिता ने बताया कि यूटी कांगरी पर सफलता उनके एवरेस्ट मिशन की प्रारंभिक तैयारी का एक पायदान है। उनके इस मिशन में दिल्ली सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक राज्यों के 11 सदस्य थे। इनमें से 2 लोग पहले से ही एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं।
- उन्होंने बताया कि 4700 मीटर ऊँचाई पर स्थित उनके बेस कैंप में माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तापमान था। अंतिम चढ़ाई के समय यह माइनस 31.4 डिग्री तक कम हो गया था। शिखर पर चढ़ाई के दौरान 50 कदम पहले ही अचानक एवलांच (बर्फ के बड़े टुकड़े का गिर जाना) आ गया था।
- अमिता श्रीवास की उपलब्धियों को देखते हुए ज़िला प्रशासन द्वारा यूटी कांगरी में पर्वतारोहण के लिये 80 हज़ार रुपए प्रदान किये गए। इससे पहले उनके पर्वतारोहण को प्रोत्साहित करने के लिये सीएसआर मद से 2 लाख 70 हज़ार रुपए पर्वतारोहण के लिये प्रदान किये गए थे।

राज्यपाल ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक पर किये हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

- 20 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (क्र. 19 सन 1956) में संशोधन हेतु प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- इस अधिनियम की धारा 12 में संशोधन किया गया है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 (क्र. 19 सन 1956) की धारा 12-क की उपधारा (2) के परंतुक में, अंक '65' के स्थान पर, अंक '70' प्रतिस्थापित किया जाए। अर्थात् इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति की आयु सीमा 65 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष होगी।
- यह अधिनियम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

मुख्यमंत्री ने जशपुर के पर्यटन और जैव-विविधता पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया

चर्चा में क्यों ?

- 21 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में जशपुर के पर्यटन और जैव-विविधता पर आधारित वर्ष 2022 के कैलेंडर तथा दैनिक समाचार-पत्र 'आज की जनधारा'के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- जैव विविधता पर आधारित इस कैलेंडर में जशपुर ज़िले के मनोरम जलप्रपात, पर्वत, वन्य प्राणी, धार्मिक स्थलों सहित चाय बागान, एडवेंचर स्पोर्ट्स और जनजातीय जीवन के पर्व-त्योहारों के दृश्यों को शामिल किया गया है।
- न्यूज़ समूह के स्टेट हेड सुभाष मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष 'आज की जनधारा'के कैलेंडर में रंगकर्मी अरुण काठोटे के कविता पोस्टर संकलित किये गए हैं।
- कैलेंडर में सर्वश्री गजानन माधव मुक्तिबोध, विनोद कुमार शुक्ल, धूमिल, नागार्जुन, पाब्लो नेरुदा सरीखे हिन्दी और विश्व साहित्य के जनवादी कवियों की प्रसिद्ध रचनाओं को शामिल किया गया है। साथ ही जाने-माने साहित्यकारों, कलाकारों की जयंती सहित शासकीय अवकाश की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने राजधानी में किया छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन के कार्यालय का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 23 जनवरी, 2022 को नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में नवगठित 'छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन'की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन के राज्य स्तरीय कार्यालय का राजधानी रायपुर में शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोज़गार के नए अवसरों के सृजन की दिशा में तेजी से काम करने और नियमित रूप से रोज़गार मिशन के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि उद्योगों और बाज़ार की मांग के अनुसार युवाओं को रोज़गार के लिये तैयार किया जाए, उन्हें प्रशिक्षण देकर विभिन्न ट्रेडों में दक्ष बनाया जाए।
- उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बाज़ार की मांग के अनुसार उत्पादन किया जाए। इन उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और सर्टिफिकेशन के लिये छत्तीसगढ़ में स्थित उच्च तकनीकी संस्थानों का सहयोग लिया जाए। नए स्टार्टअप के लिये बेहतर इको-सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे युवाओं को रोज़गार के बेहतर अवसर मिल सकें।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में आगामी पाँच वर्षों में रोज़गार के 12 से 15 लाख नये अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन का गठन किया है।
- प्रमुख सचिव कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोज़गार एवं छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.आलोक शुक्ला ने बैठक में छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन पर प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र की प्रगति, गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, गोधन न्याय योजना, लघु वनोपजों के संग्रहण और वेल्यू एडिशन से रोज़गार के अवसर बड़े पैमाने पर निर्मित हुए हैं। शासकीय और निजी क्षेत्र में भी लोगों को बड़ी संख्या में रोज़गार मिला है, जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी की दर घटकर मात्र 2.1 प्रतिशत रह गई है।
- डॉ. शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ रोज़गार मिशन रोज़गार से संबंधित विभिन्न विभागों-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, मत्स्य पालन, हार्टीकल्चर, वन, उद्योग, ग्रामोद्योग, नगरीय प्रशासन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास कार्यक्रम, गौठान, गोधन न्याय योजना, बाड़ी योजना और टी-कॉफी बोर्ड के कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करेगा।
- यह मिशन रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण, सेवा तथा उत्पादन क्षेत्रों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग, निजी कंपनियों के साथ सहयोग कर रोज़गार के बेहतर अवसरों के निर्माण के दिशा में काम करेगा। मिशन द्वारा छत्तीसगढ़ के बेहतर उत्पादों और सेवाओं के संबंध में शोध को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्टार्टअप के लिये बेहतर इको-सिस्टम निर्मित करने में सहयोग करेगा।
- यह रोज़गार के नए अवसरों को निर्मित करने के लिये इको-पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन, होम-स्टे, फूड प्रोसेसिंग, वनौषधि, हस्तशिल्प और कोसा व रेशम का बेहतर मार्केट बनाने के लिये काम करेगा।

मुख्यमंत्री ने किया कहानी संग्रह 'विशिष्ट पराग' का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 23 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में सुश्री कोमल पुरोहित धनेसर के कहानी संग्रह 'विशिष्ट पराग'का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि पत्रिका अखबार के भिलाई संस्करण में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत सुश्री कोमल पुरोहित धनेसर ने पत्रकारिता की शुरुआत बस्तर से की थी।

नोट :

- बस्तर में रहते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ में पदस्थ पैरामिलिट्री बल के जवानों के जीवन को करीब से देखने का मौका मिला। इसी दौरान उन्होंने इस किताब को लिखना शुरू किया।
- डिप्टी कमांडेंट चिकित्सा अधिकारी डॉ. तारकेश्वर नाथ इस पुस्तक के सह-लेखक हैं।
- उन्होंने इस किताब में संकलित 11 कहानियों के माध्यम से पैरामिलिट्री बल के पराक्रमी अधिकारियों और जवानों के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया है, जो आम तौर पर लोगों के सामने नहीं आ पाते।

पीएमजीएसवाइ में सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

- 24 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) में सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस ऑनलाइन बैठक में विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।
- छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति के बारे में बताया कि प्रदेश में योजना के पहले, दूसरे और तीसरे फेज के अंतर्गत कुल 42 हजार किमी. से अधिक की 8547 सड़कें स्वीकृत हैं।
- नक्सल प्रभावित इलाकों में कुल 176 किमी. लंबाई की 38 सड़कों के निर्माण के लिये निविदा स्वीकृत हो गई है। शेष 277 किमी. की 54 सड़कों के लिये पुनर्निविदा की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है।
- उन्होंने बताया कि सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण एवं प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किये गए हैं, जिनमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में राज्य को 5612 किमी. लंबाई की सड़क आवंटित थी। इन सभी सड़कों की स्वीकृति दो चरणों में प्राप्त कर राज्य प्रथम रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण मार्च 2022 तक पूर्ण हो जाएगा।
- उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2000 किमी. लंबाई की अतिरिक्त सड़क मंजूर करने का आग्रह किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में केंद्रांश एवं राज्यांश 60:40 के अनुपात में आवंटन की तरह ही सड़कों के नवीनीकरण और संधारण के कार्यों में भी 60:40 के अनुपात में आवंटन लागू करने का आग्रह किया।
- प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ई-पोर्टल पर चार नए मॉड्यूल शुरू किये गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के लिये स्वीकृत दस लाख 97 हजार आवासों में से आठ लाख 23 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया है।

गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी कई नई सौगातें

चर्चा में क्यों ?

- 26 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर ज़िला मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश के दौरान कई नई घोषणाएँ कीं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ हैं-
  - अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिये इसी वर्ष एक व्यावहारिक, सरल एवं पारदर्शी कानून बनाने की घोषणा।

नोट :

- रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिये भी आवश्यक प्रावधान किये जाने की घोषणा।
- प्रदेश में नगर निगम से बाहर के ऐसे क्षेत्र, जो निवेश क्षेत्र में शामिल हैं, वहाँ 500 वर्गमीटर तक का भवन विन्यास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तय समय-सीमा में जारी किये जाने की घोषणा।
- नगरीय-निकायों में नल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को 'डायरेक्ट भवन अनुज्ञा' की तर्ज पर मानवीय हस्तक्षेप मुक्त बना कर समय-सीमा में नल कनेक्शन दिये जाने की घोषणा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भी शासकीय पट्टे की भूमियों को फ्री होल्ड किये जाने की घोषणा। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आबादी, नजूल एवं स्लम पर स्थित पट्टों को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया था, अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक नीति में संशोधन कर इस प्रवर्ग हेतु दस प्रतिशत भू-खंड आरक्षित किये जाने की घोषणा। यह भू-खंड भू-प्रीमियम दर के दस प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 'मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना'की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में किये जाने की घोषणा।
- युवाओं की सहूलियत के लिये लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने की घोषणा। इसके लिये बृहद् स्तर पर 'परिवहन सुविधा केंद्र'प्रारंभ किये जाएंगे। इन केंद्रों को न केवल लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु अधिकृत किया जाएगा, अपितु इन केंद्रों में परिवहन विभाग से संबंधित समस्त सेवाएँ नागरिकों को अपने निवास के पास मिल सकेंगी एवं प्रदेश के युवाओं को रोज़गार का अवसर मिलेगा।
- शासकीय कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किये जाने की घोषणा।
- शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिये 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करने की घोषणा।
- महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए हर ज़िले में 'महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ' के गठन की घोषणा।
- तीरंदाज़ी को प्रोत्साहित करने के लिये जगदलपुर में 'शहीद गुंडाधूर'के नाम पर राज्यस्तरीय तीरंदाज़ी अकादमी प्रारंभ करने की घोषणा।
- वृक्ष कटाई के नियमों की जटिलता एवं इसके कारण वृक्षारोपण में नागरिकों की अरुचि को देखते हुए नागरिकों के हित में इससे जुड़े कानून के सरलीकरण की घोषणा की। इसके लिये सभी प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाएंगे।
- आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 से दलहन फसल जैसे- मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किये जाने की घोषणा।
- श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोज़गार, स्वरोज़गार तथा विवाह में सहायता के लिये 'मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना'शुरू किये जाने करने की घोषणा की। इस योजना के तहत 'छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल' में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हज़ार रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
- सभी ज़िला मुख्यालयों तथा विकासखंड स्तर पर 'मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र' और प्रत्येक विकासखंड में आईटीआई खोले जाने की घोषणा की।

श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर में उपलब्ध दवाओं की मूल्य सूची पुस्तिका का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 26 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में नगर निगम, रायपुर के अंतर्गत संचालित श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर की दवाई रेट लिस्ट एवं मेडिकल आइटम सूची का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर की बुकलेट में रायपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी जेनेरिक मेडिकल दुकानों के पूरे पते सहित किस बीमारी के इलाज के लिये कौन-सी दवाई व सामान उपलब्ध होगा, इस संबंध में आसान भाषा में जानकारी दी गई है।

नोट :

- बीमारी से संबंधित दवाई का प्रकार, दवाई का नाम, एमआरपी मूल्य और छूट देने के बाद दवा की कीमत को चार्ट के माध्यम से बुकलेट में प्रदर्शित किया गया है। साथ ही गूगल मैप के द्वारा श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर का पता खोजने और मेडिकल स्टोर हेल्पलाइन संबंधित जानकारी के साथ ही जिन फार्मा कंपनियों की दवाई और मेडिकल सामान यहाँ उपलब्ध रहेंगे, उनके नाम भी सूचीबद्ध किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि लोगों को सस्ती दरों में दवाई उपलब्ध कराने के लिये छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर समेत प्रदेश के कई स्थानों में श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत की है।
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना में 251 प्रकार की जेनेरिक दवाइयाँ तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य रखी गई है। इसके अलावा वन विभाग के संजीवनी के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद और शिशु आहार आदि के विक्रय का भी प्रावधान है।

राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और बहादुर बच्चों को किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 26 जनवरी, 2022 को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पुलिस परेड ग्राउंड में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक अलंकरण से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा राज्यपाल ने राज्य वीरता पुरस्कार से कोरबा के मास्टर अमन ज्योति जाहिरे एवं धमतरी ज़िले के मास्टर शौर्य प्रताप चंद्राकर को सम्मानित किया।
- राज्यपाल ने 21 पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया। इनमें कमलोचन कश्यप (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बीजापुर), सुरेश लकड़ा (उप पुलिस अधीक्षक, रायगढ़), संजय पोटाम (उप निरीक्षक, दंतेवाड़ा), लक्ष्मण केंवट (निरीक्षक, राजनांदगांव), ओंकार सिंह दीवान (उप निरीक्षक, कोण्डागांव), बीजाराम तामो (प्रधान आरक्षक, बीजापुर), उमा शंकर राठौर (निरीक्षक, रायपुर), चेतन लाल बेलेन्द्र (प्रधान आरक्षक एसटीएफ बघेरा, दुर्ग) तथा मानिक लाल कोरेटी (प्रधान आरक्षक, सुकमा) शामिल हैं।
- इसी प्रकार मोहन लाल निषाद (निरीक्षक, बीजापुर), बृज लाल भारद्वाज (निरीक्षक बिलासपुर), कमलेश कुमार रात्रे (सहायक प्लाटून कमांडर एटीएफ बघेरा, दुर्ग), सोमारू राम यादव (आरक्षक, सुकमा), आशीष सिंह राजपूत (उप निरीक्षक, बलौदाबाजार), इंद्र कुमार शिवानी (कंपनी कमांडर एसटीएफ बघेरा, दुर्ग), विन्टन कुमार साहू (निरीक्षक, बलौदाबाज़ार), अश्वनी राठौर (उप निरीक्षक रायपुर), जीतेंद्र कुमार डहरिया (उप निरीक्षक, राजनांदगांव), दिनेश पुरेना (उप निरीक्षक, राजनांदगांव), विरासत कुजूर (उप निरीक्षक, बीजापुर), शहीद मुरली ताती (सहायक उप निरीक्षक, बस्तर) को भी पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया।
- राज्यपाल ने विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति के पुलिस पदक से उदयभान सिंह चौहान (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी पुलिस मुख्यालय रायपुर) को सम्मानित किया।
- राज्यपाल ने 10 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया। इनमें यदुराम तिर्की (उप पुलिस अधीक्षक एसटीएफ, बघेरा दुर्ग), मनीष परमानंद (उप पुलिस अधीक्षक, सरगुजा), श्रीराम वर्मा (सहायक सेनानी, बीजापुर), डिलेश्वर प्रसाद साहू (उप निरीक्षक, रायगढ़), अवधेश कुमार चौहान (उप निरीक्षक, कांकेर), प्रेमसाय भगत सहायक (उप निरीक्षक, रायगढ़), दृगपाल प्रसाद तिवारी (प्रधान आरक्षक दुर्ग), प्रहलाद सिंह गागड़ा (प्रधान आरक्षक, जगदलपुर), मदनमोहन पटेल (प्रधान आरक्षक, सकरी बिलासपुर), अवकाश राम नरेटी (प्रधान आरक्षक, कांकेर) शामिल हैं।
- राज्यपाल ने 6 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया। इनमें सुरेश प्रसाद गौतम (चीफ इंस्ट्रक्टर, नगर सेना रायपुर), मोती लाल साहू (सब इंस्पेक्टर, नगर सेना रायपुर), भोगेंद्र गोग (हवलदार, नगर सेना, दंतेवाड़ा), जोधन लाल साहू (हवलदार, नगर सेना, बलौदाबाज़ार), रेणु लोखेण्डे (लांस नायक, नगर सेना, रायपुर), सुरेंद्र देवांगन (सैनिक, नगर सेना, राजनांदगांव) शामिल हैं।

नोट :

- राज्यपाल ने 7 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को यूनियन होम मिनिस्टर मेडल से सम्मानित किया। इनमें श्रीरोद्र कुमार साहू (उप निरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर), गंगा धुर्वे (निरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर), कन्हैया लाल यादव (प्रधान आरक्षक, 11 सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज कांकेर), गंगा प्रसाद यादव (प्रधान आरक्षक, क्र.149 राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी), कन्हैया लाल यादव (प्रधान आरक्षक, 6 सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज कांकेर), जीत कुमार देवांगन (सूबेदार, राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर), कमलेश कुमार सोनबोईर (उप निरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव) शामिल हैं।
- इसके अलावा राज्यपाल ने दो जेल प्रहरियों को सराहनीय सुधार सेवा पदक से सम्मानित किया। इनमें संतराम पुरेना (ज़िला जेल बेमेतरा) तथा लेखराम धुरंधर (केंद्रीय जेल रायपुर) शामिल हैं।

प्रदेश में सबसे अधिक रायगढ़ जिले के 279 गोठान हुए स्वावलंबी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में जारी आँकड़ो के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से महत्त्वपूर्ण 'सुराजी गाँव योजना' के 'गरूवा' घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 7933 गोठानों में से 2201 गोठान स्वावलंबी हो गए हैं। रायगढ़ ज़िले में सर्वाधिक 279 गोठान स्वावलंबी हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

- दूसरे नंबर पर महासमुंद एवं कोरबा ज़िले में 170-170 गोठान स्वावलंबी हुए हैं। स्वावलंबी गोठान गोबर खरीदी से लेकर वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के लिये स्वयं के पास उपलब्ध राशि का उपयोग करने लगे हैं।
- गौरतलब है कि राज्य में पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक 10591 गाँवों में गोठान के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 7933 गोठानों का निर्माण पूरा हो चुका है और वहाँ पर गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट के निर्माण सहित अन्य आयमूलक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं।
- वर्तमान में 2300 गोठानों का तेज़ी से निर्माण कराया जा रहा है, शेष 358 गोठानों के निर्माण का कार्य अभी शुरू कराया जाना है। गोठानों में पशुधन की देखरेख, चारे-पानी एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
- रायगढ़ ज़िले में गोठान संचालन के लिये आवश्यक सभी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। गोठान में संलग्न कर्मचारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी व वर्मी कंपोस्ट निर्माण एवं उसके विक्रय की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। इन सामूहिक गतिविधियों का परिणाम रहा कि रायगढ़ ज़िले में प्रदेश में सबसे अधिक 279 गोठान स्वावलंबी बने।
- इसके साथ ही गोठानों में अन्य आयमूलक गतिविधियों को मल्टीएक्टीविटी सेंटर के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते गोठान में कार्यरत् महिला समूह अतिरिक्त आय सृजित कर रहे हैं।

रायपुर जिले में कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू

चर्चा में क्यों ?

- 30 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को चिह्नित करने और कुष्ठ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये 'स्पर्श कुष्ठ जन जागरूकता पखवाड़ा' शुरू किया गया। इसका समापन 13 फरवरी को होगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि भारत में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (30 जनवरी) के अवसर पर कुष्ठरोग से संबंधित कलंक एवं भेदभाव को समाप्त करने तथा लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिये 'कुष्ठ विरोधी दिवस' मनाया जाता है।
- अभियान की शुरुआत करते हुए डॉ. फिरोज खान (अधीक्षक, सरकारी कुष्ठ केंद्र, पंडरी, रायपुर) ने कहा कि समाज में फैला अंधविश्वास कुष्ठ को पिछले जन्म से होने वाले पाप के रूप में देखता है। समाज से बहिष्कृत होने के डर से बीमारी को छिपाकर रखने वाले लोग वास्तव में बीमारी फैलाते हैं।

नोट :

- उन्होंने कहा कि लोगों को यह समझने की जरूरत है कि कुष्ठ एक इलाज योग्य बीमारी है और अगर इसमें देरी की गई तो इससे प्रभावित अंगों में विकलांगता और विकृति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जीवाणु रोग होने के कारण यह छूने से नहीं फैलता है, लेकिन मरीज की जल्द पहचान और इलाज की जरूरत है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कुष्ठ रोग के प्रति ग्रामीणों में भय व भ्रांतियों को दूर करने और जागरूकता पैदा करने के लिये ग्राम स्तर पर 'ग्राम सभा' का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्ण रूप से ठीक हुए कुष्ठ रोगी को अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाएगा।
- गाँवों में कुष्ठ रोग और उसके इलाज के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये प्रचार वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा। कुष्ठ रोग के लक्षणों की जाँच के लिये एक टीम डोर-टू-डोर ड्राइव करेगी।
- विदित हो कि छत्तीसगढ़ में कुष्ठ रोग की प्रसार दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 2.45 है। प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम दर लाने का लक्ष्य रखा गया है।

शहीदों के सम्मान में रायपुर में प्रज्ज्वलित होगी 'छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति'

चर्चा में क्यों ?

- 29 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के सम्मान में राजधानी रायपुर में 'छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति' का निर्माण कराने की घोषणा की। इसका भूमि पूजन सांसद राहुल गांधी के हाथों आगामी 3 फरवरी को किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 'छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति' का निर्माण चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना, रायपुर के परिसर में किया जाएगा। शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति अनवरत जलती रहेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जिन सपूतों ने वर्दीधारी सेवाओं में जाकर देश के लिये प्राण न्यौछावर किये, साथ ही छत्तीसगढ़ में देश भर के जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनकी शहादत का सम्मान 'छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति' के माध्यम से किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि सन् 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के शहीद वीर सैनिकों के सम्मान में नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति प्रज्ज्वलित की थी, जो 1972 से लगातार जलती आ रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट कर दिया।
- छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति में शहीदों की नामावली सूची की दीवार, मेमोरियल टावर एवं वीवीआइपी मंच भी तैयार किया जाएगा। शहीदों की नामावली सूची की दीवार का निर्माण ब्राउन मार्बल से एवं शहीदों के नाम को उसी मार्बल में खुदाई कराकर लिखा जाएगा। यह दीवार लगभग 25 फीट ऊँची एवं लगभग 100 फीट की लंबाई के अर्धचंद्राकार रूप में रहेगी। इस दीवार की मोटाई 3 फीट होगी।
- मेमोरियल टावर की स्थापना अर्धचंद्राकार दीवार के सामने बलुआ पत्थर ब्राउन व्हाइट मार्बल ग्रेनाइट से की जाएगी। इसके शीर्ष में स्मृति चिह्न का निर्माण कराया जाएगा।
- मेमोरियल टावर के सामने आधार पर राइफल एवं हेलमेट प्रतीक चिह्न के रूप में रहेगा। इसी प्रतीक चिह्न के सामने 'छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति' प्रज्ज्वलित होगी, जो भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से ईंधन सप्लाई द्वारा 24 घंटे जलेगी।
- मेमोरियल टावर के ठीक सामने किलानुमा दो मंजिला भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस भवन के आधार की लंबाई 150 फीट, चौड़ाई 90 फीट एवं ऊँचाई 40 फीट होगी। उक्त भवन के सामने 16 बिगुलरों के खड़े होने के लिये 16 गुंबदों का निर्माण कराया जाएगा।
- इस भवन के प्रथम तल पर शहीदों की चित्र प्रदर्शनी एवं द्वितीय तल पर शस्त्र प्रदर्शनी रखी जाएगी। इस इकाई में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय पुलिस स्मृति दिवस के दौरान सम्मिलित शहीदों के परिजनों के ठहरने हेतु सर्व सुविधा युक्त मेस एवं आवासीय कमरों का निर्माण कराया जाएगा।

नोट :